अवैध निर्माण क्यों छोड़ दिए

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। निगमायुक्त मोना ए श्रीनिवास ने प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर पांच निर्माणाधीन इमारतों को सील करवा दिया और उन पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हाईकोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों को लागू करवाने के लिए निगमायुक्त का यह कदम ठीक है लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी अन्य उपायों को भी पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। शहर की वायु गुणवत्ता बीते कई सप्ताह से अत्यंत खराब है। ऐसी हालत में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए निगम की महती जिम्मेदारी है। कूड़े कचरे के ढेर में आग लगाने की घटनाओं पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना, सड़कों की सफाई मशीनों से कराना, सभी सड़कों पर पानी का छिड़काव कराना, निर्माण कार्य पर पूर्णतया प्रतिबंध जैसे उपाय प्रमुख हैं। निगमायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण पर कार्रवाई के नाम पर निर्माणाधीन इमारतों को तो सील करा दिया लेकिन शहर में जगह जगह रोजाना कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है उस पर काबू नहीं किया गया। मुख्य सड़कों पर छिड़काव तो गाहे बगाहे ही कराया जाता है जबकि इन हालात में लगातार छिड़काव कराने की आवश्यकता है। मशीनों से झाड़ू की व्यवस्था भी गिने चुने इलाकों में लागू है, ऐसे में वायु की गुणवत्ता में सुधार क्या होगा समझा जा सकता है।

निगमायुक्त ने वैध रूप से बन रही इमारतों को तो सील करवा दिया लेकिन उनके कर्मचारियों को वो अवैध निर्माणाधीन इमारतें नहीं दिखीं जो निगम कर्मचारियों की मिलीभगत से बनाई जा रही हैं। एनआईटी के इलाके में जगह जगह अवैध रूप से निर्माण कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं लेकिन उन पर न तो निगम के तोड़फोड़ दस्ते की नजर पड़ती है और न ही निगमायुक्त की। केवल इमारतें सील करने का ड्रामा करने से वायु की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी इसके लिए ईमानदारी से सभी जरूरी उपाय लागू किया जाना जरूरी है।

पुलिस आयुक्त आर्य ने मंत्री का हुक्म बजाया....

पेज एक का शेष

इधर पुलिस आयुक्त अपराधियों पर कार्रवाई करने का दबाव बना रहे थे। इस पर सुनील कुमार 20 नवंबर की शाम सोनू को बुलाने गए। सोनू नहीं मिला तो घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो के मालिक अनिल कुमार को अनखीर चौकी ले आए थे। पीछे से सोनू का बड़ा भाई भी चौकी आ गया। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार सोनू के भाई ने जांच अधिकारी से अभद्रता की और परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली। चौकी में सरकारी कार्य में बाधा डालने और अभद्रता करने पर सुनील कुमार ने युवक को समझाया लेकिन उसका तेवर बिगड़ता गया।

शांत नहीं होने पर सुनील कुमार ने उसे थप्पड़ मार कर ढंग से बात करने की नसीहत दी। बड़ा भाई नतीजे भुगतने की धमकी देता हुआ चौकी से चला गया। चौकी इंचार्ज ने भी अगले सोमवार तक आरोपी को जांच में शामिल कराने की नसीहत देकर अनिल कुमार को छोड़ दिया। बताया जाता है कि सोनू के भाई के कहने पर केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर के कार्यालय से पुलिस आयुक्त राकेश आर्या को फोन कर पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने का आदेश दिया गया था।

फिर क्या था, थोड़ी ही देर में पुलिस आयुक्त राकेश आर्या के कार्यालय में चौकी इंचार्ज और आईओ को तलब होने का फरमान सुना दिया गया। दोनों पेश हुए तो सीपी ने दोनों को जमकर लताड़ लगाई, मानो वह सरकारी अफसर न होकर गूजर के नौकर हों। बिना कोई सफाई सुने सुनील कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। चौकी इंचार्ज ने जांच अधिकारी का पक्ष लेकर उसका बचाव करना चाहा तो सीपी महोदय ने कहा तुम भी लाइन जाओ। सोमवार रात को ही दोनों को अनखीर चौकी से रिलीव कर लाइन रवाना कर दिया गया।

साहब के फरमान से ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले पुलिसकर्मियों का मनोबल टूट गया है। नाम न छापने की शर्त पर कई पुलिसकर्मियों का कहना था कि निष्पक्ष रूप से काम करना बड़ा मुश्किल है खास कर मेवला महराजपुर इलाके व मंत्री के सजातीय गुडों की आपराधिक घटनाओं पर। सीपी, डीसीपी और एसीपी सभी अपराध पर काबू करने का हुक्म सुनाते हैं लेकिन अपराधियों को काबू करने के बाद नेताओं का फोन आने पर यही अधिकारी पलटी मार जाते हैं।

दूसरी ओर राज्य के गृहमंत्री अनिल विज मुकदमे लंबित रखने वाले तफ्तीशियों को निलंबित करने के आदेश बढ़-चढ़ कर देते हैं। वे यह जानने का प्रयास कतई नहीं करते कि मुकदमे लंबित रहने के असली दोषी उनकी पार्टी के नेतागण व कायर उच्चाधिकारी ही होते हैं। मौजूदा मामले से सबक लेते हुए यदि सुनील व ओम प्रकाश जैसे पुलिस कर्मी गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध मुकदमा ही दर्ज न करें तो शहर की क्या स्थिति होगी? संदर्भवश, सुभाष यादव की बतौर सीपी तैनाती के दौरान, मंत्री गूजर के ऐसे ही सजातीय बंधुओं ने जब थाना ओल्ड में घुस कर गुंडागर्दी की थी तो पुलिस ने उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाया था। उस समय सुभाष यादव ने मंत्री गूजर की परवाह न करते हुए डट कर अपने मातहतों का साथ दिया था।

दलालों से मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों पर पीएमओ मेहरबान

पीड़ित महिला का आरोप लगाते हुए वीडियो देखने के बाद भी लिखित शिकायत के बिना कार्रवाई से किया इनकार

निजी लैब की दलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीमा (बाएं), अस्पताल परिसर में रंजू का ब्लड सैंपल लेता निजी लैब का कर्मचारी, पीएमओ सविता यादव (दाएं) को नजर नहीं आते

शेखर दास

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। फरीदाबाद बीके अस्पताल में ओपीडी काउंटर से लेकर अस्पताल के अंतिम छोर तक विभिन्न प्रकार के दलालों का बोलबाला है या यूं कहें की उनकी मजबूत पकड़ है, मजबूत भी इतनी की पेशेंट डॉक्टर से बाद में मिलता है दलाल की मुलाकात पहले हो जाती है। इसका मुख्य कारण हैं डॉक्टरों से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कइ कर्मचारियों का इन दलालो के एजेंट के रूप मे काम करना। यह बात किसी से छुपी नही है, इसी कारण इन दलालो का ग्रुप अस्पताल परिसर स्थित पुलिस चौकी से लेकर पीएमओ के कार्यालय तक देखने को मिल जाता है।

एसजीएम नगर निवासी रंजू देवी पित्त की थैली में पथरी की समस्या का इलाज कराने 21 नवंबर को बीके अस्पताल आई थी। डॉक्टर ने उपचार हेतु ब्लड व ईसीजी की जांच लिखी थी जिसे वह अस्पताल के अलग-अलग काउंटर पर जाकर करवा रही थी। सर्वविदित है कि अस्पताल में न तो डॉक्टरों द्वारा लिखी सभी दवाएं मिल पाती हैं और न ही सभी जांच यहां हो पाती हैं। इसी का फायदा यहां के दलालों के एजेंट उठाते हैं। इस अस्पताल में अपना इलाज करवाने आए अधिकतर मरीज गरीब तबके के और कम पढ़े लिखे होते हैं। इसी कारण दलाल इन्हें आसानी से फंसा लेते हैं, ऐसा ही रंजू देवी के साथ भी हुआ। जब वह अपने ब्लड की जांच के लिए गई तो वहां बताया गया कि कुछ जांचें बाहर से होंगी।

ईसीजी जांच की रिपोर्ट लेते वक्त इसी रूम में बैठी दलालों की एजेंट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीमा से रंजू ने पूछ लिया कि यह ब्लड जांच कहां होगी। ये कर्मचारी इसी ताड़ में रहते हैं कि कोई इनसे कुछ पूछ ले और ये उसे दलालों के हवाले कर दें। सीमा को अपना ग्राहक मिलते ही उसने तुरंत दुकानदारी शुरू कर दी और रंजू से कहा कि यह जांच बाहर 800 रुपये में होती है, मैं इसे 600 रुपयों में करा दूंगी। रंजू ने 500 रुपये देने की बात कही, सौदा तय हो गया। रंजू के पास पैसे पूरे नहीं थे, उसने 200 अभी देने और बाकी 300 रुपये रिपोर्ट लेते वक्त देने की बात कही। सीमा ने मंजूर करते हुए तुरंत अपने मोबाइल से कॉल करके दलाल को अस्पताल में बुला लिया और रंजू से कहा की अस्पताल के बाहर जाकर अपने ब्लड का सैंपल दे दो। जब वह दलाल रंजू का ब्लड सैंपल ले रहा था, संवाददाता की नजर उस पर पड़ गई। संवाददाता ने उससे पूछ लिया की यह क्या कर रहे हो? इस पर दलाल बौखला गया और हावी होने की कोशिश करने लगा और संवाददाता ने जब उसे समझाया तो दलाल ने नौ दो ग्यारह होने में समय नहीं लगाया।

संवाददाता ने जब रंजू से पूछा कि आप यहां पर ब्लड सैंपल क्यों दे रहे हो तो उसने आपबीती बताई। इस पर संवाददाता ने कहा कि मुझे उसके पास ले चलो जिसने तुम्हें इस दलाल से मिलवाया था। जब रंजू के साथ ईसीजी रूम में पहुंचे तो वहां पर एजेंट सीमा बैठी मिली, जिसे रंजू ने पहचान लिया और जब उससे पूछा गया तो वह हड़बड़ा गई और तरह-तरह की सफाई देने लगी।

इस पूरे मामले की शिकायत जब अस्पताल की पीएमओ सविता यादव से की गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो इन लोगों से तंग आ चुकी हूं, अस्पताल में पूरी तरह से इन दलालों की भरमार है, पर इनकी पहचान कैसे हो यह बड़ा मुश्किल है। हजारों की तादाद में यहां लोग आते हैं। इनमें यह दलाल भी होते हैं और अगर मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं भी तो कैसे? कोई मुझे लिखित में शिकायत देता ही नहीं है और बिना लिखित शिकायत के मै असहाय हूं।

बेलसोनिका यूनियन के संघर्ष को समर्थन देने पहुंची जन अभियान-दिल्ली की टीम

गुड़गांव (मज़दूर मोर्चा) बेलसोनिका यूनियन के संघर्ष के साथ एकजुटता जताने व समर्थन देने जन अभियान-दिल्ली की टीम 19 नवंबर को धरना स्थल डीसी आफिस गुड़गांव पहुंची। बेलसोनिका यूनियन के बहादुराना संघर्ष की सराहना करते हुए जन अभियान-दिल्ली के घटक संगठनों के प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। इस मौके पर डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट के साथी अर्जुन प्रसाद, सीपीआई (एमएल) क्रांतिकारी पहल के साथी विमल त्रिवेदी, लोकपक्ष के साथी कृष्ण कान्त, मजदूर सहयोग केंद्र की साथी गौरी, इंकलाबी मजदूर केंद्र के साथी मुन्ना प्रसाद ने संघर्षरत मजदूर साथियों को संबोधित किया। इनके अलावा इस एकजुटता कार्यक्रम में सीपीआई (एमएल) क्रांतिकारी पहल के कामरेड उमाकांत एवं अन्य करीब एक दर्जन से अधिक साथियों की भी भागीदारी हुई।

बात यह है कि गुड़गांव स्थित बेलसोनिका कम्पनी की मजदूर यूनियन ने कम्पनी में स्थाई काम पर लम्बे समय से कार्यरत एक ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता दी तो कम्पनी मैनेजमेंट और हरियाणा श्रम विभाग ने मिलकर यूनियन का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया है। मजदूरों द्वारा मैनेजमेंट व श्रम विभाग की क्रूर कार्रवाई की ख़िलाफत करने पर कई यूनियन पदाधिकारियों व सदस्यों को निलंबित अथवा बर्खास्त कर दिया गया है। कम्पनी यूनियन द्वारा मजदूरों के अधिकारों पर हो रहे घृणित हमले के खिलाफ 12 अक्टूबर से गुड़गांव डीसी कार्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन श्रम विभाग व सरकार की नींद नहीं खुल रही है।

साथियों आज के कठिन दौर में बेलसोनिका यूनियन का ठेका मजदूरों को जोड़ने की पहल और उनका संघर्ष सराहनीय है। शोषण उत्पीड़न के खिलाफ वर्गीय एकता बनाकर संघर्ष करना ही एकमात्र सही तरीका है। हम सभी को ऐसे संघर्षरत मजदूरों के साथ खड़े होना होगा। %जन अभियान-दिल्ली% दिल्ली में मजदूरों-मेहनतकशों के बीच काम करने वाले क्रांतिकारी व जनवादी संगठनों का मंच है। यह मंच मजदूरों-मेहनतकशों, दलितों, महिलाओं व सभी तरह के दबे-कुचले लोगों की आवाज उठाता है, तथा उनके न्यायपूर्ण संघर्षों में एकजुटता के साथ समर्थन करता है। इसी कड़ी में मंच ने बेलसोनिका यूनियन के संघर्ष को समर्थन देने का कार्यक्रम तय किया था।